

हाईवे चैनल

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले पहलगाव हमले के दोषियों को बख्शेंगे नहीं, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (न्यूज चैनल)। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाव हमले को लेकर दुःख जताया और साथ ही पहलगाव के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पहलगाव को घटना ने देशवासियों को पीड़ा पहुंचाई है और इसे लेकर देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा है। लोग पीड़ित परिवारों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। हर भारतीय का खुद आतंक की तस्वीरों को देखकर खिल रहा है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति तैयारी रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। पर्यटकों की संख्या में अत्यंत वृद्धि बढ़ाती रही थी और लोगों

को कमाई बढ़ रही थी, जिनका देश के दुश्मनों को और जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को ये पता नहीं था। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। इस मुश्किल वक़्त में एकता सबसे बड़ा आधार है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस चुनौती को सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक बड़े गड़ के रूप में अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करना है। भारत के लोगों में जो आक्रोश है, जो पूरी दुनिया में है, उस आक्रोश को एक बड़े दुर्निवार से लगाया संवेदान्त आ रही है। कई राष्ट्राध्यक्षों ने मुझे भी फोन करके पहलगाव को घटना पर दुःख जताया है। इस जयन्त तक के



फिर आप आतंकी हमले की सभ्यते में कटोरे नियां की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ खड़ा है। 'पीड़ित परिवारों को भरपूर देता है' उन्हें न्याय मिलेगा... और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों को कड़ोरतम जवाब दिया जाएगा।

बिहार की धरती से भी पीएम मोदी ने दी थी आतंक के आकाओं को चेतवनी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोते गुवागर को बिहार की एक जनसभा में भी पहलगाव हमले के दोषियों को चेतवनी देते हुए कहा था कि आज बिहार को सख्त ससे में पूरी दुनिया से यह कहना चाहता हूँ कि भारत इन लोगों को पहचान करेगा, उन्हें पकड़ेगा और हर आतंकी तथा उनकी मदद करने वालों को सख्त देगा। हम उन्हें पूछेंगे कि अंतिम और तक बखड़े हों। भारत को आतंक को आतंकवाद कभी नहीं तोड़ सकता। इंसान मिलते, इनके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इस दुर्दिना में जो भी दुर्भावना के पक्ष में है, वह हमारे साथ है। इस दुर्दिना में जो भी हमारे साथ खड़ा है, हम उनके गुणगजार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हमला सिर्फ हिन्दू पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत को आला पर हमला करने का दुर्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकीयों को और इस हमले की सहायता देने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी। अन्य आतंकीयों की बनी-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाकर का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं को कमर तोड़कर रहेगी।

सुरक्षा बलों को मिली नक्सलियों की खुफिया गुफा सैकड़ों की संख्या में रहा करते थे माओवादी

बोयापुर, 27 अप्रैल (हाईवे चैनल)। बोयापुर और तेलंगाणा की सीमा पर स्थित करंगुटा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 5 दिनों से चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन के दौरान जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच 5 दिनों के कड़ी मशकत के बाद आखिर जवान नक्सलियों के एक ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी के निशान मिले हैं, हालांकि नक्सलियों ने सुरक्षा बल के पहुंचने से पहले ही अपना ठिकाना बदल लिया है, बताया जा रहा है कि, इस गुफा में आराम से एक हजार से अधिक लोग कई दिनों तक पनाह ले सकते हैं। गुफा के अंदर पानी से लेकर आराम करने लायक भी सुविधा मौजूद है।



गुफा के अंदर ही एक बहुत बड़ा मैदान भी मौजूद है, बता दें, उस्र थाणा क्षेत्र अंतर्गत कोटापल्ली गांव के करंगुटा पहाड़ी में लगातार 5 दिनों से सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, यह देशभर में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें 10 से 12 हजार जवानों ने बड़े कैडर के नक्सली लीडरों समेत 1500 नक्सलियों को पहाड़ी परिया में घेर रखा है, सुरक्षा बल के जवान अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 हेलीकॉप्टर से नक्सलियों पर गोलियों और बमबारी कर उनका जवाब दिया जा रहा है, मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है, निम्न में से 3 के घबरा सतेत हथियार बचाए गए हैं, आज 5वें दिन भी लगातार दोनों तरफ से रक्त-रक्त कार्रवाई हो रही है और नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की जा रही है।

साल्हेभाट-चमेदा के जंगलों में जवानों को सर्चिंग के दौरान मिला 9 बम व नक्सल सामग्री, जवानों को देख भागे नक्सली

- 3 कुकर बम, 3 डिब्बा बम, 2 पाईप बम, 1 दिफिन बम, 1 राकौ टैंकी सहित दैनिक ज़रूरी व नक्सली सामान
- नगरी डीआरजी, सीएफएवल्हारी टीम द्वारा नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता, नक्सलियों के मंसूबों फेरा पानी



आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र पांडेय के मार्गदर्शन में जिला धमतरी के नगरी डीआरजी एवं सीएफए खबरी की टीम सर्चिंग ऑपरेशन पर था। खबरी के चर्मेदा,साल्हेभाट क्षेत्र में रवाना हुई थी। इसी दौरान प्रातः लगभग 8 बजे चमेदा, साल्हेभाट के बीच जंगल में माओवादियों द्वारा डेक किया गया 3 नग कुकर बम, 3 नग पाईप बम व एक नग दिफिन बम, एक नग राकौ टैंकी और उच्चार यंत्रणा (दवाइयां), दैनिक उपयोगी वस्त्र, राशन व अन्य सामग्री जितने अलग अलग थैले की एक टिकाट डिब्बा व नीले कलर का प्लास्टिक ड्रम में डेक कर दो दो अलग-अलग जाह डेक किया गया था। जेडीएस टीम द्वारा डेक किये जाने के बाद खबरी में अज्ञात परिचित माओवादियों ने अज्ञात अपराध क्र.02/25 धारा 04,05, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 क़ानून कर विवेचना में लिया गया।

तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए मिला सदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (न्यूज चैनल)। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम की धमकी मिली है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के पीआरओ ने बताया कि हवाई अड्डे को ईमेल के जरिए धमकी मिली। वम निरोधक दलेत तिमिनल्लो को जांच कर रहे हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

तंदूपता बोनस घोडाले में निर्लांबित आईएफएस अधिकारी अशोक पटेल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

रायपुर, 27 अप्रैल (हाईवे चैनल)। अंतरासाह के वृत्तनिर्वाह तंदूपता बोनस घोडाले में आर्थिक अपराध अधिनियम शाखा की विशेष कोर्ट ने अशोक पटेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने पटेल को दो बार पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। बता दें, अशोक पटेल को 6 करोड़ रुपए के तंदूपता बोनस घोडाले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उनकी संतुष्टि प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निर्लांबित कर दिया था। पटेल छत्तीसगढ़ के पहले आईएफएस अधिकारी हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है।



तंदूपता बोनस घोडाले छत्तीसगढ़ में तंदूपता संग्रहण और बोनस वितरण से जुड़ा एक बड़ा मामला है, जिसमें अनियमितताओं और गवर्न के आरोप सामने आए हैं।

ईओडब्ल्यू को जांच में अग्रणी पटेल की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस मामले में कई तंदूपता सफलता के प्रबंधकों के डिजानों पर भी ज़ोरधारी की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जम्बू किए गए। जांच एजेंसी ने पुष्टा सबूत ज़ूटाए और आगे की कार्रवाई की गई।

ब्रेकिंग न्यूज

सोमवार को छातीसगढ़ में नहीं होगी रजिस्ट्री, पंजीवन कार्यालय रहेगें बंद

रायपुर, 27 अप्रैल (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में सभी पंजीवन कार्यालय सोमवार (28 अप्रैल) को बंद रहेगें, इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में पंजीवन कार्य बंद रहेगा, रजिस्ट्री बंद रहने से प्रदेशभर में करीब 15,000 से अधिक लोगों को असुविधा होने की संभावना जताई जा रही है, पंजीवन विभाग ने अपॉइंटमेंट बक करने वाले पक्षकारों को पहले ही सैसज कर जानकारी दे दी है और नगरिकों से सहयोग की अपील की है। जानकारी के मुताबिक, रजिस्ट्री के साथ-साथ सफलता नामांकरण की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिए अप्रकारियों को जूटिया भी जारी है। इसके अलावा, पंजीवन कार्यालयों में नई गाइडलाइन तैयार करने और जर्मनों के नए गाइडलाइन रेट को समीक्षा का काम भी किया जाएगा।

ओपन परीक्षा में 10वीं का पेपर लीक, 3 अधिकारी निलंबित

गिरवांचंद, 27 अप्रैल (हाईवे चैनल)। फिनेर विकासखंड के लोहरसी परीक्षा केंद्र में ओपन स्कूल को परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, 12वीं कक्षा के गुरु विद्यालय को परीक्षा में गलती से 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया, मामले को गंभीरता से लेते हुए उप संचालक लोकेश कुमार संचालनवाय छत्तीसगढ़ ने कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, निलंबित अधिकारियों में केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह, निरीक्षक, सहायक केंद्राध्यक्ष सुनील राम यादव और जिला प्रतिनिधि आंखवंर नीलू शाह शामिल हैं, निलंबन आदेश के दौरान सभी को जिला शिक्षा कार्यालय गिरवांचंद में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए।

दिल्ली में रह रहे पांच हजार पाकिस्तानी, आईबी की लिस्ट से सामने आया हैरान करने वाला आकड़ा, पुलिस को सौंपी सूची

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (न्यूज चैनल)। पहलगाव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सख्त अपनाया। पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए कई सख्त सरकारी ने उनके राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान लाने सामने लगी है। दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है। भारत के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इनकी लिस्ट सौंपी है। आईबी ने दिल्ली में रह रहे करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है ताकि इन लोगों की घर-घरों सूनिहित की जा सके। विदेशी शेषासी एजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने यह सूची दिल्ली पुलिस को विशेष शाखा के साथ साझा की है और आगे सत्यापन और पहचान के लिए इसे संबंधित जिले के साथ भी साझा किया गया है। इस सूची में उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के नाम शामिल हैं जिनके पास दैनिकी के वीजा (एलटीवी) हैं और उन्हें दूट दी गई है। सूची सत्यापन के लिए संबंधित जिले की सौंप दी गई है और पाकिस्तानियों को अपने बतन लौटने को कहा गया है।

एनआईए ने हमले के चरमदीयों से की पूछताछ, हर बिंदु पर बारीकी से हो रही छानबीन

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (न्यूज चैनल)। पहलगाव आतंकवादी हमले की जांच राष्ठीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई है। एक्सपर्ट एजेंसी के एक पुलिस उपनिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक की अग्रवार्द में गैरट टीएम ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाव में अज्ञात घाटी में हुए हमले के चरमदीयों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एजेंसी ने पहलगाव आतंकी

हमला को जांच शुरू की है।

अधिकारियों ने बताया कि घटनाक्रम को कड़ियों को जोड़ने के लिए चरमदीयों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। एनआईए आतंकीयों के प्रवेश और निकास बिंदुओं को बारीकी से जांच कर रही है। फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से टीम पर

ताबतौड खोपे मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर में साक्ष्य 14 स्थानों आतंकीयों को सूचीबद्ध की गई है। ये आतंकी पाकिस्तानी दशहतादों को रख व जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षा बलों को हिरासत में कर रहे हैं। इनमें तीन हिजबूल मुजाहिदीन, आठ लश्कर और तीन जेश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। अधिकारियों ने बताया, शुक्रवार रात पुलिसवा, शोपिया व कुलामन में आतंकीयों के घर घबस्त किए गए।

सिब्वल की अपील: पहलगाव हमले को लेकर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाए

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (न्यूज चैनल)। निलंबीय राजसया सांसद कॉपिल सिब्वल ने रायपुर को राजनीतिक दलों से विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों पहलगाव आतंकी हमले के महत्तर माई में जलद संसद का विशेष सत्र बुलाने का सरकार से आग्रह करें। सिब्वल ने कहा, 9/25 अप्रैल को मेरी सुझाव दिया था कि इस दुःख को घड़ी में देख को एकता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि संसद से माई में जलद से जलद ऐसा सत्र बुलाने का आग्रह करें।

सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी सुझाव दिया था, ताकि पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन की संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि जिस तरह अमेरिका अपने प्रतिबंधों के साथ करता है, उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध रखने वाले सभी प्रमुख देशों से कहना चाहिए कि अगर उनका इस्लामावाद के साथ व्यापार है तो वे भारतीय बाजार में नहीं आ सकते। इससे उन्हें विनिर्भर दलों के नेताओं ने नई दिल्ली में आतंकवाद और आतंकी शिविरों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई का आग्रह किया था। उन्होंने सरकार को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया था। पहलगाव हमले पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने कहा था कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। सरकार ने नेताओं को आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को दी बड़ी सौगात

रायपुर, 27 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बड़ा देने के लक्ष्य में विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, निवेशकों को विनिर्भर आवश्यक सुवीकृतियां और सेवाएं अब तय समय-समया में प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही, कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित भी कर दिया गया है, जिसे औद्योगिक विकास को नए मिलेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य बनाना हमारा प्राथमिकता है, औद्योगिक विकास से न केवल राज्य को अर्थव्यवस्था सख्त होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे, हमारी सरकार निवेशकों को लक्षित, पारदर्शी और जनसहकृत सेवाएं उपलब्ध कराने की संकल्पित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खतरनाक तथा अन्य अपरिष्कृत प्रबंधन के तहत अनुसूचित प्रदान करने के लिए 60 दिन, बायो-मैफिकल अपरिष्कृत प्रबंधन हेतु एस्कलेटर भी कर दिया गया है, जिसे अपरिष्कृत प्रबंधन हेतु स्वीकृत के लिए 30 दिन और निर्माण एवं विन्यस अपरिष्कृत प्रबंधन हेतु अनुमति के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है, इसी तरह नदी या सार्वजनिक जलाशयों से जल दोहन हेतु अनुमति 300 दिनों में प्रदान की जाएगी, जबकि जल आवृत्ति एजेंसी से जल को अनुपलब्धता प्रश्नक प्रमाण पर 90 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। भवन निर्माण से संबंधित पांच चरणों जैसे भवन योजना स्वीकृति, परिचरिता या पुनरीक्षण की अनुमति, खसलांकण एवं पुनर्निर्माण की अनुमति, लिंथ तंत्र स्वीकृति तथा अधिभोग/पूजा प्रमाण पर के लिए अधिकतम 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है, इसी प्रकार लिफ्ट और एस्कलेटर को स्थापना हेतु अनुमति, नवीनीकरण और निरीक्षण के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है, स्टार्ट-अप इकाइयों के पंजीकरण के लिए भी 45 दिनों की समय-सीमा तय की गई है, इसके अलावा, निवेशकों को सुविधा में लया, उन्हे आदेश प्रमाण एवं सार्वजनिक निर्माण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, सेवा क्षेत्रों के इकाइयों के प्रश्नों का समाधान भी 7 दिनों में और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों में किया जाएगा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि निवेशकों को सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निष्पत्ता छत्तीसगढ़ सरकार को प्राथमिकता है, हमें विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक नक्सल बनने में सफल होगा, गौरवचरन है कि अब तक निवेश सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था, उन्हे इस आदेश के माध्यम से अधिसूचित माना जाएगा, यह आदेश राज्य में लया, उन्हे आदेश प्रमाण एवं सार्वजनिक निर्माण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को सुविधा में लया, उन्हे आदेश प्रमाण एवं सार्वजनिक निर्माण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि निवेशकों को सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निष्पत्ता छत्तीसगढ़ सरकार को प्राथमिकता है, हमें विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक नक्सल बनने में सफल होगा, गौरवचरन है कि अब तक निवेश सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था, उन्हे इस आदेश के माध्यम से अधिसूचित माना जाएगा, यह आदेश राज्य में लया, उन्हे आदेश प्रमाण एवं सार्वजनिक निर्माण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, सेवा क्षेत्रों के इकाइयों के प्रश्नों का समाधान भी 7 दिनों में और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों में किया जाएगा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि निवेशकों को सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध निष्पत्ता छत्तीसगढ़ सरकार को प्राथमिकता है, हमें विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक नक्सल बनने में सफल होगा, गौरवचरन है कि अब तक निवेश सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था, उन्हे इस आदेश के माध्यम से अधिसूचित माना जाएगा, यह आदेश राज्य में लया, उन्हे आदेश प्रमाण एवं सार्वजनिक निर्माण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।